experienced the heaviest shortage of 30%—32%, while Haryana had 5% to 8% and U.P. had 11% to 12% shortage. Delhi, H.P., Punjab and Chandigarh experienced a shortage of less than 5%. The main reason for power shortage in the Northern Region is the increase in demand and less availability of thermal power from stations of UPSEB and HSEB.

(b) and (c) Various measures taken to improve the availability of power in the Northern Region include expediting commissioning of new generating capacity, improving performance of existing capacity, reduction in transmission and distribution losses, implementation of demand management and energy conservation measures etc.

In order to assist Haryana in mitigating the shortages, assistance has been extended to the State from the unallocated quota of the central generating stations and by allocating additional power from Chamera HEP. Haryana has been allocated 10% cut of the unallocated quota in NTPC stations and 26% out of unallocated power in NPC and NHPC stations except Chamera where its share has been increased to 68% of the total output as against the original share of only 4.5%.

आयकर अपवंचन

86. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:**
श्री नागमणि:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि भूमि पर आय दर्शा कर कतिपय कम्पनियों और उद्यमियों द्वारा करोड़ों रुपये के आय-कर अपवंचन के अनेक मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) भविष्य में कर अपवंचन के ऐसे मामलों की रोक-थाम के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (घ): जी, हां। खेती योग्य भूमि से प्राप्त की गई आय दिखाकर कर अपवंचन के अनेक मामले आयकर विभाग की जानकारी में आए है। चूंकि कर अपवंचन को रोकना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और मामले की जांच के विभिन्न स्तरों पर है, अतः ऐसे सभी मामलों में की गई जांचों के परिणाम उचित कार्यवाही करने और कर योग्य आय के निर्धारण के लिए कर-निर्धारण अधिकारियों को सूचित कर दिए जाते हैं।

(ङ) कर अपवंचन को रोकने के लिए सरकार समय-समय पर आवश्यक कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक उपाय करती आ रही है और उचित मामलों में सर्वेक्षणों, तलाशियों और अभियोजनों आदि का सहारा लिया जाता है जिससे कर अपवंचन का पता लगाया जा सके।

Replacement of Energy inefficient Agricultural Pumping Sets

87. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the agricultural pumping sets being installed at present and in use all over the country are energy inefficient;

(b) whether it is also a fact as per a latest study, atleast 20,000 MW energy can be saved if these pumps are replaced; and

(c) if so, reasons for delay in replacing these pumps?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) to (c) A large number of studies have pointed out that the pump sets used in irrigation are not energy efficient. Studies have indicated that there is considerable potential for energy savings in the energy consumption if the inefficient pump sets are rectified or replaced by energy efficient ones. Majority of pump sets in the country are purchased by farmers directly. Considering that power is provided at virtually no cost to

the agricultural sector by the State Govts., the farmers do not realise the potential for energy savings through more energy efficient pump sets. The State Electricity Boards and the farmers are being educated on energy efficiency in the pumping systems. The Govt. of India has also given assistance to the State Electricity Boards and other organisations, for rectification of pump sets. The State Govts. are also being urged upon to levy agricultural tariff in order to encourage farmers to use energy efficient pump sets.

पकड़ा गया काला धन

88. **श्री नागमणि:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान अब तक पकड़े गए काले धन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भविष्य में काले धन का पता लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान जनवरी, 1996 तक आयकर विभाग ने 35476.72 लाख रुपये की लेखाबाह्य परिसम्पत्तियों को पकड़ा है।

(ख) कानून के उपबंधों के अनुसार कर अपवंचकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना सरकार की घोषित नीति है। चूंकि कर अपवंचन रोकना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः कर अपवंचन को रोकने के लिए सरकार तलाशी एवं अभिग्रहण, सर्वेक्षण एवं अभियोजन जैसे विभिन्न कदम उठाती है।

विश्व बैंक द्वारा सहायता

89. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने राजस्थान में कृषि विकास परियोजना की सफलता से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में अन्य अनेक परियोजनाओं का वित्तपोषण करने का प्रस्ताव किया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं तथा उनके लिए प्रस्तावित सहायता की राशियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र हेतु कृषि विकास परियोजनाओं का बैंक से संभावित वित्तपोषण किए जाने के लिए विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। विश्व बैंक की सहायता की राशि सहित परियोजनाओं के ब्यौरों का पता परियोजनाओं को अंतिम रूप दिये जाने के बाद ही चलेगा।

Reservation of SC/ST in Nationalised Banks

90. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that reservation for SC/ST has been made upto Grade I officers only in all the nationalised banks in the country and there is no reservation in Grade II to IV of the bank officers;

(b) if so, the details and reasons therefor; and

(c) whether Government propose to make reservation in all the Grades of Banks Officers, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) Reservation for SC/ST personnel exists in the case or promotion from clerical cadre to level of Scale I (JMGS-I) officers in public sector banks. Reservation does not exist in the case of promotion from Scale I onwards to next higher scales in cases involving promotion by selection method.

(b) and (c) The guidelines and policies framed by Government with regard to reservations for SCs & STs in Government service are adopted by public sector banks broadly in the same manner as it is